हर घर जल
जल जीवन मिशन

मिलकर करें काम
बनाएं जीवन आसान

जल जीवन संवाद

नवंबर, 2020

मिशन निदेशक की कलम से.....

नई दिल्ली
27 नवंबर, 2020

2024 तक भारत देश के प्रत्येक घर को पाइप के जरिए जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। इससे विशेषकर महिलाओं और किशोरियों के जीवन यापन में सुधार होगा क्योंकि पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पानी लाना उनकी ही जिम्मेदारी समझी जाती है। जल जीवन मिशन में नल कनेक्शनों की कार्यशीलता पर फोकस किया जा रहा है अर्थात नियमित एवं दीर्घकालीक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक घर को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। पिछले 15 महीनों में कोविड-19 महामारी के बावजूद काफी अच्छी प्रगति हुई है। 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के समय से लेकर अब तक लगभग 2.67 करोड़ परिवारों को नए नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब तक लगभग 5.90 करोड़ परिवार, जो देश के कुल ग्रामीण परिवारों का 31% है, अपने घरों में नल से जल प्राप्त कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत सार्वभौमिक कवरेज पर फोकस किया जा रहा है और इस प्रकार गोवा सभी ग्रामीण परिवारों को 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक देश में 18 जिलों, 400 से अधिक ब्लॉकों, 31,000 ग्राम पंचायतों और 56,000 गांवों के प्रत्येक घर में जल आपूर्ति प्राप्त हो गई है।

बच्चे जल जनित बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं इसलिए सभी स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनवाड़ियों में पाइप के माध्यम से जल कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 2 अक्टूबर, 2020 को 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य पीने और मध्यान भोजन पकाने तथा हाथ धोने एवं शौचालय उपयोग के लिए सुरक्षित एवं स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन स्थानों में हमारे बच्चों को पाइप के जरिए स्वच्छ पेयजय प्रदान करने के लिए कठिन परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंता और गांव कार्यकर्ता इस वर्ष के अंत तक गुणवत्ता प्रभावित गांवों में स्वच्छ जल का प्रावधान करने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में बहु-विषयक टीम को नियुक्त करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहायता का भी विस्तार किया गया है। राज्यों द्वारा सुखा-ग्रस्त/ठंडे मरूस्थल/ठोस चट्टानों/पहाड़ी/समुद्री क्षेत्रों जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और उनके समाधान की तलाश की गई है। यह सब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु आपसी भागीदारी और मिलकर कार्य करने से हो पा रहा है।

कार्य की मध्य-वर्षीय समीक्षा की गई थी। विस्तृत समीक्षा में देखा गया है कि अलग-अलग राज्यों और क्षेत्र-वार भिन्न-भिन्न चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल मुहैया कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए देश भर में 7,000 गांवों में कार्यशीलता मूल्यांकन किया जा रहा है। ग्रामीण घरों को निर्धारित मात्रा में पर्याप्त गुणवत्ता के साथ पेयजल की नियमित आपूर्ति की पहुंच के लिए नमूना परिवारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जिला क्लेक्टर/उप आयुक्त के संचालन के अंतर्गत जिला प्रशासन इस कार्यक्रम का मुख्य आधार है। जिला का कार्यनिष्पादन, जिले के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सावधानीपूर्वक योजना तैयार करके डीएम/डीसी द्वारा किए जा रहे नेतृत्व और मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। वे रोडमैप तैयार करते हैं और मिशन के लक्ष्य अर्थात दीर्घकालीक पेयजल सुरक्षा को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी तालमेल के लिए इस कार्यक्रम के तहत जुड़े विभिन्न सहायक विभागों के साथ समन्वय करते हैं।

जल जीवन मिशन-हर घर जल कार्यक्रम पूरे समाज एवं समुदाय के व्यवहार परिवर्तन लाने वाला 'जन आंदोलन' है। मिशन का उद्देश्य समुदाय को संगठित करने, क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं के क्षमता विस्तार और वर्ष 2024 तक 100% एफएचटीसी प्राप्त करने में सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स, स्व:सहायता समूहों, स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी करना है। जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति कार्य करते समय हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क के उपयोग, हाथ धोने और शारीरिक दूरी बनाए रखने को ध्यान में रखना है। इस समय, इस वैश्विक महामारी से प्रसार को रोकने का एकमात्र यही प्रभावी तरीका है।

(भरत लाल)
अपर सचिव एवं मिशन निदेशक
जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन

15 अगस्त, 2019 को स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन को एंड-टू-एंड उपायों के साथ एकीकृत अवधारणा के साथ तैयार किया गया है: स्रोत की आपूर्ति से पुन:-उपयोग और रिचार्ज तक। 'हर घर जल' कार्यक्रम की परिकल्पना 'जन आंदोलन' – लोगों का आंदोलन के रूप में की गई है।

जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन राज्यों की भागीदारी में किया जा रहा है ताकि वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराने के लिए गांवों में प्रत्येक ग्रामीण घर को समर्थ बनाया जा सके। जेजेएम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां ग्रामीण भारत में महिलाओं और बालिकाओं द्वारा सामना किए जा रहे कड़े श्रम से मुक्ति दिलानी है जो अपने प्रतिदिन की घरेलू आवश्यकताओं के लिए पीने योग्य जल लाने हेतु प्रतिदिन दूर चलकर पानी लाने का काम करती हैं।

विज़न

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को **नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा** में पेयजल आपूर्ति मुहैया करना जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

मौजूदा परिपेक्ष्य:

- गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन उपलबध कराने वाला पहला राज्य बन गया है;
- 98% कवरेज के साथ तेलंगाना राज्य 100% एफएचटीसी कवरेज के करीब आ गया है;
- फिलहाल, भारत में ग्रामीण परिवारों के 31% के पास नल जल कनेक्शन उपलब्ध है;
- 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास 31% ग्रामीण एफएचटीसी का औसत से अधिक प्रतिशतता है;
- 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से नीचे है;

जादुई संख्या तक पहुंचने वाले राज्य:

- पुडुचेरी, गुजरात, हरियाणा और सिक्किम ने ग्रामीण परिवारों में 70% से अधिक एफएचटीसी के साथ उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है;

राज्य जिन्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता है:

- विशाल भूमि क्षेत्र और आबादी वाले प्रमुख राज्य जिन्हें वर्ष 2024 तक 100% एफएचटीसी प्राप्त करने के लिए अधिक आवश्यक गति लाने की आवश्यकता होगी, वे राज्य हैं: कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

.

देश में प्रगतिशील एफएचटीसी कवरेज

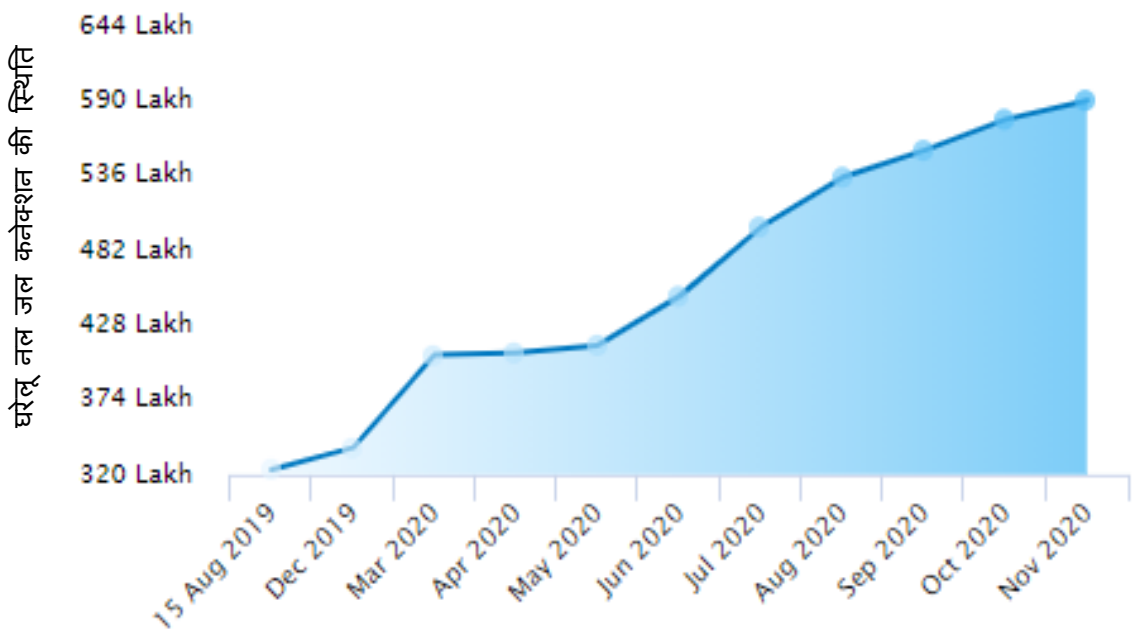

घरेलू नल जल कनेक्शन की स्थिति

15 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार

27 नवंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार

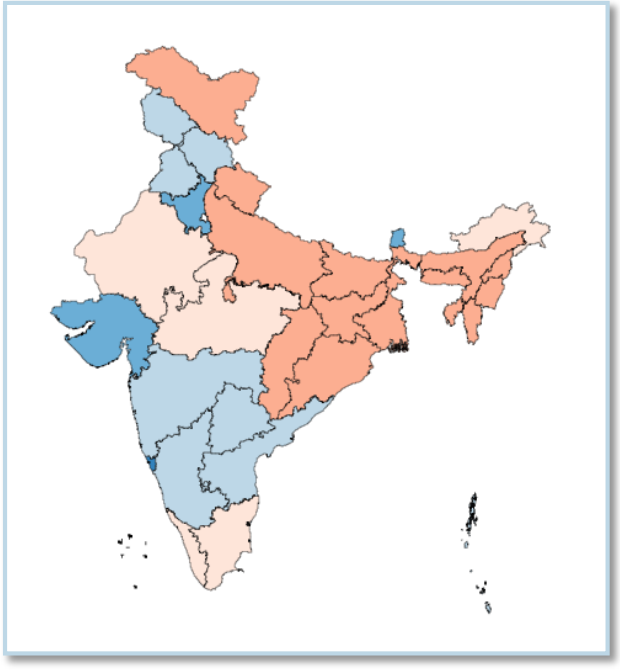

0%-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-<100% | 100%

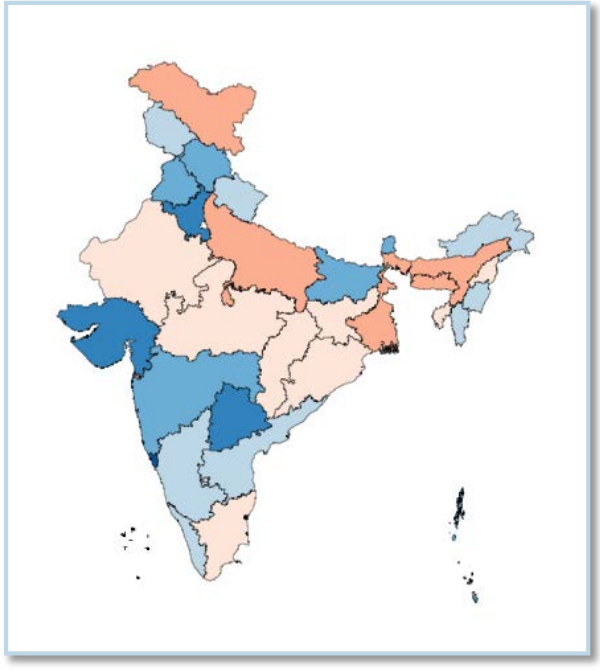

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 22 नवंबर, 2020 को मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के 2,995 गांवों को लाभ देने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और जल शक्ति और नमामि गंगे राज्य मंत्री, डॉ. महेन्द्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित हुए। 5,555.38 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य मिर्जापुर और सोनभद्र की 42 लाख आबादी को लाभ प्रदान करते हुए 2,995 गांवों में घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करना है।

जन मानस को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा, "आजादी के बाद दशकों तक, अगर कोई भी क्षेत्र उपेक्षा का शिकार हुआ है, तो यह यही क्षेत्र था। विंध्याचल हो या बुंदेलखंड, यह पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बना हुआ है। इतनी सारी नदियाँ होने के बावजूद, इस क्षेत्र को सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था। यही कारण था, जिसने कई लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया ... यह माताओं, बहनों और बेटियों के लिए खुशी का क्षण है क्योंकि यह योजना लोगों के दर्द और पीड़ा को दूर करेगी।"

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा, "पिछले एक-डेढ़ साल में जल जीवन मिशन की शुरुआत से, देश में 2.60 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया गया है... जल की सुविधा आसान होने के चलते माताओं और बहनों का जीवन बेहतर हो रहा है। यह योजना गंदे पानी पीने से होने वाली हैजा, टाइफाइड और इंसेफेलाइटिस जैसी कई बीमारियों को कम करने वाली है। विन्ध्याचल के हजारों गाँवों में पाइप के जरिए पानी पहुँच जाने के बाद, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होगा।"

उन्होंने कहा, इन सभी गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां कार्यक्रम के तहत बनाई गई बुनियादी सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूह सदस्या के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत में उनसे अनुरोध किया कि वे पानी के संरक्षण का संदेश फैलाएं क्योंकि हर घर में पाइप का पानी का मतलब जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन लाना भी है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, सोनभद्र जिले के लिए 3,200 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएँ और मिर्जापुर के लिए 2,355 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाएँ क्षेत्र के ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं। परियोजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम को प्रसारित किया गया था। परियोजनाएं दो साल के भीतर यानी वर्ष 2022 तक पूरी कर ली जाएंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान महिलाओं और बालिकाओं के कड़े श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए मददगार होगा क्योंकि पानी लाना उनकी ही जिम्मेदारी समझी जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का 'का जीवन यापन सुगमता से होगा। चूँकि मिशन का उद्देश्य सर्वव्यापी कवरेज है, इसलिए बस्ती/गाँव में प्रत्येक परिवार को नल जल कनेक्शन मुहैया करना है और यह सुनिश्चित करना है की 'कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रहे। हमारे देश के लोगों की **'जीवन की गुणवत्ता में सुधार'** और 'जीवन यापन की सुगमता' सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जल जीवन मिशन देश के हर ग्रामीण घर तक पीने के पानी की बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। पिछले 15 महीनों के दौरान, कोविड महामारी के बावजूद 2.63 करोड़ घरों में नल का जल कनेक्शन दिया गया है और वर्तमान में लगभग 5.86 करोड़ (30.67%) ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध हो गए हैं।

India | Status of tap water supply in rural homes

Total number of households	Households with tap connections as on 15 Aug 2019	Households with tap connections as on date
		+71,073
19,10,85,542	3,23,62,838 (16.94%)	5,89,57,635 (30.85%)

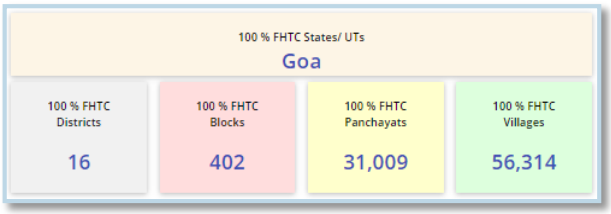

100 % FHTC States/ UTs			
Goa			
100 % FHTC Districts	100 % FHTC Blocks	100 % FHTC Panchayats	100 % FHTC Villages
16	402	31,009	56,314

"जब विंध्यांचल के हजारों गांवों में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनका शारीरिक और मानसिक विकास और बेहतर होगा। इतना ही नहीं, जब शुद्ध पानी मिलता है तो कुपोषण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, पोषण के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसके भी अच्छे फल इसके कारण मिल सकते हैं।"

- नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

ग्राम जलापूर्ति अवसंरचना हेतु स्थानीय समुदायों को उनकी ग्राम पंचायतों अथवा इसकी उप समितियों अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समितियों आदि के माध्यम से अपनी जलापूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन, अनुमोदन, रख-रखाव करना है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की सीमांत, समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सहित सभी परिवारों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है, जिससे 'कोई भी परिवार वंचित न रहे', का सिद्धांत बरकरार रहेगा। यह स्थानीय समुदाय के बीच अपनत्व की भावना' और गर्व भी पैदा करेगा।

गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना

गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने अपने दो जिलों के सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया है।

गोवा में तटीय क्षेत्र होने के कारण पानी की बहुत अच्छी उपलब्धता है। राज्य के लोग इसके महत्व को स्वीकार करते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करके अर्थव्यवस्था में पानी की भूमिका को समझते हैं। गोवा में होटल के अलावा ग्रामीण बस्तियों और गाँव पर्यटकों को ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं, और सभी ग्रामीण घरों में पाइप कनेक्शन के माध्यम से पानी की नियमित आपूर्ति समुदाय को आगंतुकों को 'घर में रहने' की सुविधा प्रदान करने में मदद करती है। तथापि, गोवा ने अपनी वार्षिक कार्ययोजना के तहत वर्ष 2021 तक 100% पाईप जलापूर्ति प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन पीएचईडी अधिकारियों और ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए गति, पैमाने और सावधानीपूर्वक कार्य ने उन्हें निर्धारित समय से पहले लक्ष्य हासिल करने में मदद की है। गोवा ने पीने के पानी के स्रोतों के सुदृढीकरण, जल आपूर्ति प्रबंधन, मनरेगा और ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) निधि के तहत मौजूदा संसाधनों का तालमेल किया है।

गोवा में, सभी जल आपूर्ति कनेक्शनों के साथ पानी के मीटर लगाए गए हैं, और जल बिलिंग को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। प्रत्येक उपभोक्ता को आसान भुगतान विकल्प के साथ एक कम्प्यूटरीकृत बिल प्राप्त होता है। गोवा ने 'ऑन द स्पॉट बिलिंग' की शुरुआत करके ग्रामीण समुदाय के लिए सेवा सुधार सुविधा भी शुरू की है, जिससे दीर्घकालिक आधार पर राजस्व संग्रह और नियमित पेयजल आपूर्ति में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

गोवा में पेयजल आपूर्ति के निर्वहन और कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए आईओटी आधारित सेंसर निगरानी प्रणाली को लागू करने की योजना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता के साथ नियमित और दीर्घकालिक रूप से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा सके। राज्य में एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी है और उन्हें जन सामान्य के लिए जल परीक्षण सुविधाओं हेतु खोला जाना है। प्रत्येक गाँव के पाँच व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं को गाँवों में आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। नियमित परीक्षण से अपनत्व की भावना के निर्माण के साथ-साथ बेहतर सेवा वितरण की मांग में मदद मिलेगी।

इस छोटे से राज्य ने प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने योग्य पानी की सुनिश्चित सेवा वितरण के लिए दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन सभी राज्यों से इस तरह की प्रतिबद्धता की अपेक्षा करता है।

स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइप के जरिए जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए 100 दिवसीय अभियान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर देश के सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइपगत जलापूर्ति प्रदान करने के लिए 2 अक्तूबर, 2020 को एक 100 दिवसीय अभियान की शुरूआत की गई थी। बच्चों को सुरक्षित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार के लिए प्राथमिकता है और इससे बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास में सुधार होगा। यह अभियान इन संस्थानों में पीने और मध्यान भोजन व् हाथ धोने और शौचालय के उपयोग के लिए सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति प्रदान करने का एक अवसर है। ऐसे सभी स्थानों में, विशेष रूप से सूखाग्रस्त और जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में ग्रे-वाटर शोधन और स्व-स्थाने पुन: उपयोग और वर्षा जल संचयन का भी प्रावधान किया गया है।

"

.....जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से एक और अभियान शुरू करने जा रहा है।

100 दिन का एक विशेष अभियान, जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनबाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं।

"

- नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस आदर्श पहल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के 15वें वित्त आयोग अनुदान, मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान के साथ-साथ विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं के समन्वय से निधियों का तालमेल करने का अनुरोध किया गया है।

शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के वास्तविक वातावरण और स्वच्छता का स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अ स्वच्छ वातावरण, पीने योग्य पानी की कमी, दूषित पानी का उपयोग, और अनुचित स्वच्छता प्रथाएं शिशुओं और छोटे बच्चों में बाल रोग और मृत्यु दर के प्रमुख कारण हैं।

इस अभियान के लिए लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग/ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/स्थानीय समुदाय/गैर-सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता समूह से मदद की अपेक्षा है। परिणाम तभी दिखाई देंगे जब अभियान एक 'जन आंदोलन' में तब्दील होगा।

उत्तम स्वच्छता व्यवहार मानव-से-मानव संचरण को रोकता है और कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करता है। उचित स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करना, पीने योग्य पेयजल प्रदान करना, और सुरक्षित, स्वच्छ व्यवहार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। जब बच्चे स्कूल लौटते हैं और ज्यों ही विद्यालय पुनः खुल जाते हैं उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारी ज़िम्मेदारी है।

अक्टूबर से जनवरी तक, तीन महीने की अवधि का उपयोग स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों को तैयार करने, योजना बनाने और उन्हें संवेदनशील करने के लिए किया जाएगा ताकि बच्चों को महीनों तक घर पर रहने के बाद उनकी वापसी पर एक स्वच्छ और सुरक्षित शिक्षण वातावरण प्राप्त हो सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि 100 दिन के अभियान अवधि के तहत सभी स्कूलों, आश्रमशालाओं, और आंगनवाड़ी में सुरक्षित पानी की पहुँच हो, इसके लिए ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्राम सभाओं के साथ सामुदायिक विचार-विमर्श किया जाए और एक योजना तैयार की जाए।

इस अभियान के माध्यम से, जल जीवन मिशन का लक्ष्य 15 लाख स्कूलों और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को पेयजल के तहत कवर करना है। इसके अलावा, इस संस्थान का उपयोग पानी से संबंधित पहलुओं यथा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल आपूर्ति, ग्रे-वाटर प्रबंधन, स्वच्छता, साफ-सफाई आदि के शिक्षण केंद्र के रूप में किया जा सकता है।

गांवों में पेयजल आपूर्ति के मापन और निगरानी हेतु सेंसर-आधरित आईओटी प्रणाली

-श्री सिद्धान्त मेसन
सीनियर प्रोग्राम मैनेजर , (टी.सी.आई.टी)

जल जीवन मिशन (जेजेएम) का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर को 'कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन' प्रदान करना है। यह मिशन 55 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य सर्वव्यापी कवरेज है अर्थात् बसावट/गांव के प्रत्येक परिवार को नल जल कनेक्शन प्राप्त हो और कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे।

जेजेएम स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर जोर देता है, जिसमें भूजल स्तर पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और ग्रे-वाटर शोधन और पुनः उपयोग आदि जैसे स्रोत स्थिरता के लिए स्थानीय अवसंरचना का निर्माण शामिल हैं, अतः इसका फोकस न केवल नल कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु अवसंरचना का निर्माण करना है बल्कि यह सेवा-प्रदान करना भी है जिसके लिए नलों की कार्यशीलता सुनिश्चित की जानी है।

हाल की तकनीकी प्रगति (जैसे कि आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, एआई/एमएल, क्लाउड) और मोबाइल डेटा, हार्डवेयर (सेंसर) और सॉफ्टवेयर की घटती लागत, ग्रामीण भारत में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को डिजिटल बनाने का अवसर प्रदान करती है। पानी की आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता और अवधी की निगरानी के लिए आईओटी आधारित प्रणाली को कार्यरत करने का अवसर है। जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के डिजिटलीकरण से जल आपूर्ति संबंधित कई समस्याओं को हल करने की क्षमता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान और पता लगाने में मदद मिलेगी।

जल जीवन मिशन के अनुसार ग्रामीण जल योजनाओं की सेवा वितरण का पता लगाने के लिए, एक 'आईओटी सेंसर-आधारित निगरानी प्रणाली' विकसित की जा सकती है जिनमें क्षेत्रीय स्थानों से डाटा एकत्रित किए जा सकते हैं और उनका वास्तविक समय में जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी करने के लिए इंजीनियरों, अधिकारियों और समुदाय द्वारा उनका उपयोग किया जा सकेगा। इससे त्वरित प्रतिक्रिया, न्यूनतम सेवा वितरण आउटेज, न्यूनतम पानी का ह्रास, और मात्रा तथा गुणवत्ता की निगरानी हो सकेगी। इस डेटा का अतिरिक्त लाभ समय के साथ उपयोगकर्ता समूहों के डिमांड पैटर्न का विश्लेषण करना है और इस जानकारी का उपयोग समग्र स्तर पर मांग प्रबंधन करने, डेटा-संचालित योजना सुनिश्चित करने और गांवों में जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रभावी संचालन और रखरखाव के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने सेंसर-आधारित माप और निगरानी प्रणाली के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसने स्टार्ट-अप्स, शिक्षाविदों तथा कॉरपोरेट को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भागीदारी में आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है, ताकि ग्रामीण भारत के स्मार्ट जल प्रबंधन के लिए नवाचारी समाधान विकसित किया जा सके। इन पहलों के अलावा, कई गैर सरकारी संस्थाएं और संगठनों ने सुदूर ग्रामीण गांवों (जैसे टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव्स ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट्स, ग्राम विकास आदि) में प्रायोगिक योजनाओं की शुरुआत की है। गुजरात सरकार वर्तमान में 500 गांवों में एक प्रायोगिक योजना का संचालन कर रही है और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए आईओटी आधारित समाधान को कार्यरत करने के लिए एक सार्वजनिक निविदा शुरू की है। इसी प्रकार, बिहार सरकार ने भी जल आपूर्ति योजनाओं में आईओटी आधारित सेंसर स्थापित करना शुरू कर दिया है।

यह आईओटी सेंसर-आधारित ग्रामीण जल निगरानी प्रणाली समुदायों को लंबे समय तक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए केपीआई का पता लगाकर "एक उपयोगिता मानसिकता विकसित करने" में मदद करेगी। आईओटी आधारित रिमोट मॉनिटरिंग से आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे कई आयामों में सभी हितधारकों (सरकार, उपयोगिता और नागरिकों) को लाभ होने की संभावना है।

यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य संचालन और अनुरक्षण की कम लागत, योजना की विफलता से बचने और समुदाय पर कम लागत के बोझ (स्वास्थ्य देखभाल के खर्च और ह्रासित मजदूरी) के माध्यम से बहुत कुछ बचा सकते हैं। इस आईओटी आधारित समाधान में ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करने और जल जीवन मिशन की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक बनने की प्रबल संभावना है।

मिलकर करें काम, बनाएं जीवन आसान: क्षेत्रगत भागीदार

जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक समयबद्ध और मिशन-मोड कार्यक्रम है। 73 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “जल संरक्षण संबंधी अभियान” केवल एक सरकारी पहल नहीं होना चाहिए बल्कि यह लोगों का आंदोलन बनना चाहिए।

वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के सफल कार्यान्वयन के लिए, मिशन जल और संबद्ध क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ साझेदारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

उन संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति मांगी गई थी जो जल क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सेक्टर भागीदार बनने के लिए व्यापक प्रभाव रखते हैं। 63 संगठनों ने अपनी गहरी रुचि दिखाई थी। इन संगठनों के साथ 28 अक्टूबर, 2020 को अपर सचिव और मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक वीडियो कान्फ्रेंस की गई थी। यह मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साझेदारी की संभावना का पता लगाने के लिए आयोजित की गई थी। ओरिएंटेशन के दौरान जल जीवन मिशन के दर्शन, लोकाचार और बुनियादी बातों को साझा किया गया। मिशन संगठनों के साथ उनकी भौगोलिक मौजूदगी, संचालन के क्षेत्र और सहयोग के लिए विषयगत वरीयताओं के आधार पर भागीदारी करेगा।

इन संगठनों ने अपने कार्यक्षेत्र, क्षेत्र में की गई गतिविधियों, विशिष्ट क्षेत्रों में मौजूदगी और विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञता जैसे सामुदाय को संगठित करना, क्षमता निर्माण, कौशल-आधारित प्रशिक्षण, आधारभूत सर्वेक्षण, जल संरक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी और पक्ष-समर्थन जैसे ब्यौरे साझा किए।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक सेवा संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं, धर्मार्थ संगठनों, और पेयजल क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों की क्षमताओं का उपयोग करना है जो जनता संगठित करने, अपनी क्षमता को बढ़ाने और प्रत्येक ग्रामीण परिवार में 100% एफएचटीसी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। इस मिशन की सफलता के लिए, सरकारी और निजी क्षेत्र, स्वैच्छिक और धर्मार्थ संगठनों सहित कॉर्पोरेट घरानों को कुशल परिणाम के लिए रणनीति विकसित करने के लिए एक साथ आना होगा। पानी को 'हर किसी का सरोकार' बनाने के लिए, मिशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भागीदारी का निर्माण करने और मिलकर काम करने का प्रयास करना है।

कार्यात्मकता मूल्यांकन

जल जीवन मिशन ने नवंबर-दिसंबर, 2020 के दौरान देश के 7,000 गांवों में फैले घरेलू नल कनेक्शनों की कार्यशीलता का आकलन करने के लिए एक शोध और सर्वेक्षण कंपनी को नियुक्त किया है। जेजेएम-आईएमआईएस के अनुसार, 30.70% ग्रामीण घरों अर्थात् देश में लगभग 19 करोड़ परिवारों में से 5.87 करोड़ परिवारों के पास पाइप के माध्यम से जल कनेक्शन उपलब्ध हैं। मिशन केवल घरेलू नल के प्रावधान के बजाय नल कनेक्शन ही नहीं अपितु उन की कार्यक्षमता पर पर भी ध्यान दे रहे है।

कार्यशीलता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

i.) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना का होना;

ii.) पर्याप्त मात्रा में नियमित आधार पर जल उपलब्ध कराना अर्थात् निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) 55 एलपीसीडी; और

iii.) दीर्घकालिक स्रोत और प्रणाली स्थायित्व जिसका तात्पर्य प्रचालन व रख-रखाव पर ध्यान केंद्रित करना है।

यह सर्वेक्षण आकार तकनीक के लिए अनुपातिक संभवतः पर आधारित होगा। प्रत्येक चयनित जिले के 10 गांव, पूरे गांव की बसावट को कवर करने के लिए पीपीएस नमूना विधि का पालन करेंगे।

प्रत्येक चयनित गांव से, 15 घरों का नमूना लिया जाएगा। एकल ग्राम जलापूर्ति योजना के तहत, 5 घरों को योजना के स्रोत से 50 मीटर के भीतर क्रम रहित आधार पर चुना जाएगा, गाँव के एक छोर से 5 घरों और गाँव के बाकी हिस्सों से 5 नमूने क्रम रहित आधार पर एकत्र किए जा सकते हैं।

एमवीएस के सर्वेक्षण के मामले में, दूरी की गणना पंपिंग बिंदु से या योजना के मुख्य पाइप के प्रवेश बिंदु से गांव तक की जाएगी। घरों का चयन करते समय यदि गाँव में विशिष्ट जाति और सम्प्रदाय के निवास करने वाले अलग-अलग आवास शामिल होते हैं, तो मूल्यांकन के लिए चयनित घरों में सभी आवासों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। यदि किसी जिले में 25% से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी है, तो 10 में से कम से कम 4 गांवों को 50% से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए चुना जाएगा।

इस कार्य को जल जीवन मिशन के समग्र मार्गदर्शन में किया जाता है। जिन स्थानों का दौरा किया जाना है उनकी रूपरेखा पहले ही विभाग द्वारा एजेंसी के साथ साझा की जाती है। सर्वेक्षण का कार्य नवंबर में शुरू हुआ और पूरे देश में महीने भर जारी रहेगा। मूल्यांकन के आधार पर, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्य-निष्पादन अनुदान प्रदान किया जाएगा।

जल जीवन मिशन पर राज्यों/ शासित राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन

केन्द्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 3 नवंबर, 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों के साथ एक आभासी (वर्चुअल) सम्मेलन की अध्यक्षता की और जल जीवन मिशन के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की।

जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री रतन लाल कटारिया, हरियाणा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों ने भी आभासी सम्मेलन में भाग लिया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस में उपस्थित थे। यह सम्मेलन सामूहिक रूप से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था, अर्थात्, योजना, कार्यान्वयन और अब तक की गई प्रगति और आगे की योजना ताकि गांवों में शेष घरों में जल्द से जल्द नल जल कनेक्शन हो। इस सम्मेलन ने कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अच्छी प्रथाओं को सीखने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य किया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक ग्रामीण घर को नियमित रूप से और दीर्घकालिक आधार पर साफ पानी मिले, जीवन को बदलने वाले इस मिशन के कार्यान्वयन को वांछित गति देने और उस गति को बनाए रखने के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने सभी राज्यों/ शासित राज्यों में मिशन की प्रगति प्रस्तुत की और मिशन के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध हो सके। केंद्रीय मंत्री द्वारा नॉलेज रिसोर्स सेंटर संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ख्यातिप्राप्त संस्थानों को इस कार्य में लगाने में मदद करेंगे।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन

जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति जल जीवन मिशन के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) मार्च, 2017 से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि मार्च, 2021 तक 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों की पहचान करके सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। एनडब्ल्यूक्यूएसएम को जल जीवन मिशन के तहत शामिल कर लिया गया है।

23.11.2020 को एनडब्ल्यूक्यूएसएम के तहत वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है:

विवरण (सं. में)	आवासों की संख्या
18.08.2016 की स्थिति के अनुसार अभिचिह्नित बसावटें	27,544
कवर की गई बसावटें	15,857
राज्य योजनाओं के माध्यम से कवर की गई/गुणवत्ता में सुधार वाली बसावटें	8,077
कवर की जा रही बसावटें	3,468
शेष बसावटें	142

आर्सेनिक प्रभावित बसावटें: एनडब्ल्यूक्यूएसएम के तहत 1.57 करोड़ की आबादी वाली 13,819 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों को लिया गया था, जिसमें से 1.40 करोड़ की आबादी वाली 11,480 बसावटें कवर की गई हैं। जल जीवन मिशन के तहत एनडब्ल्यूक्यूएसएम को शामिल करने के बाद, 4,826 आर्सेनिक से प्रभावित बसावटों की 43.85 लाख आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है। 16.97 लाख की आबादी वाली शेष 2,339 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों को कवर किया जा रहा है।

फ्लोराइड प्रभावित बसावटें: एनडब्ल्यूक्यूएसएम के तहत 1.21 करोड़ की आबादी वाली 13,725 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को लिया गया था, जिसमें से 1.13 करोड़ की आबादी वाली 12462 बसावटों को कवर किया गया है। जेजेएम के तहत एनडब्ल्यूक्यूएसएम को शामिल करने के बाद, 3,706 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की 29.46 लाख आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है। 8.12 लाख की आबादी वाली शेष 1,263 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को कवर किया जा रहा है।

"स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली" के विकास के लिए ग्रैंड चैलेंज

जल जीवन मिशन (जेजेएम), केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसे राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह घरेलू स्तर पर 'सेवा सुपुर्दगी' पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता में पानी की आपूर्ति। इसके लिए कार्यक्रम की निगरानी में और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेवा सुपुर्दगी डेटा को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है। जल आपूर्ति अवसंरचना के डिजिटलीकरण से समस्याओं का हल होने की संभावना है और साथ ही यह भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान और पता लगाने में भी मदद करेगा।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम), पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के साथ भागीदारी से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आईसीटी ग्रैंड चैलेंज के माध्यम से 'स्मार्ट जल आपूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली' विकसित करने की घोषणा की। इसके अलावा, जल जीवन मिशन ग्रैंड चैलेंज का उपयोगकर्ता एजेंट होगा। सी-डैक, बैंगलोर ग्रैंड चैलेंज की कार्यान्वयन एजेंसी है और यह चुनौती के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। सी-डैक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। यह उन्हें परामर्श सहायता, तकनीकी मार्गनिर्देश भी प्रदान करेगा।

विभिन्न राज्यों से कुल 218 आवेदन प्राप्त हुए। ये आवेदन विभिन्न क्षेत्रों जैसे एलएलपी कंपनियों, इंडियन टेक स्टार्ट-अप्स, व्यक्तियों आदि से प्राप्त हुए थे, जिनके आँकड़े निम्नानुसार थे। आवेदन 46 व्यक्तियों, 33 कंपनियों, 76 भारतीय टेक स्टार्ट-अप, 15 एलएलपी कंपनियों और 43 एमएसएमई से प्राप्त हुए थे।

आवेदनों का मूल्यांकन जारी है। विधिवत गठित जूरी के सामने शॉर्टलिस्टेड प्रस्तुतियों की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो इन ऑनलाइन प्रस्तुतियों का संचालन करेगा और प्रोटोटाइप विकसित करने के अगले दौर के लिए शीर्ष 10 की पहचान करने के लिए आवेदनों की समीक्षा करेगा।

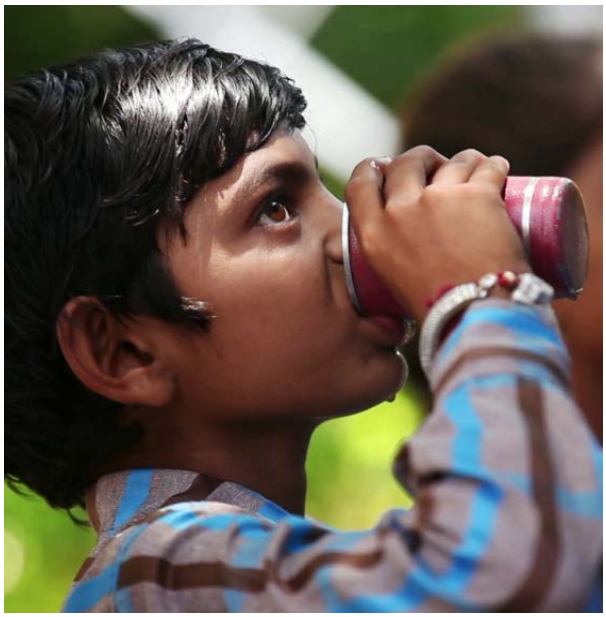

चैलेंज में आगे की कार्रवाई, अगले चरणों में प्रोटोटाइप स्टेज से आइडिशन, प्रोटोटाइप से प्रोडेक्ट स्टेज, प्रोडेक्ट डिप्लायमेंट स्टेज और तीन विजेताओं की घोषणा शामिल है। इन सभी चरणों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के वित्तपोषण सहायता से किया जाएगा। इन चरणों के मूल्यांकन के आधार पर, एक विजेता और दो उपविजेताओं का चयन किया जाएगा और विजेता को 50 लाख रु. तथा प्रत्येक उपविजेता को 20 लाख रु. दिये जाएंगे।

यह ग्रैंड चैलेंज, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की सेवा सुपुर्दगी के मापन और निगरानी के लिए स्मार्ट ग्रामीण जल आपूर्ति इको-सिस्टम बनाने के लिए भारत के वाइब्रेंट आईओटी इको-सिस्टम्स का उपयोग करेगा। यह चैलेंज जल जीवन मिशन के लिए काम करने और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आश्वासित आपूर्ति का अवसर प्रदान करेगा।

क्षेत्रीय मनोभाव

लद्दाख के ग्रामीण घरों में सुनिश्चित नल के पानी की योजना

प्रसिद्ध हिमालयन ग्लेशियर ट्रैक मार्ग और लद्दाख के राजा के महल के बीच समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्टोक गांव, लेह में सर्दियों के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा सतही जल के जमने की समस्या का समाधान हो गया है। यह अब बीते समय की बात हो गई है।

410 घरों वाला यह गाँव 7 किमी में फैला हुआ है। गाँव के लिए पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बीच में बहने वाली एक धारा है, जो सर्दियों के दौरान जम जाती है और ग्रामीणों को वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के लिए मजबूर करती है।

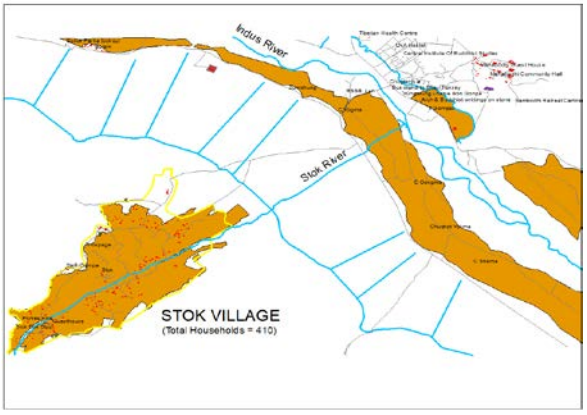

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की एक बहु-विषयक टीम ने लेह के ग्रामीण लोगों के सामने आने वाले क्षेत्रीय मुद्दों और चुनौतियों को समझने के लिए लेह की यात्रा की। पंचायत के ग्राम प्रधान, उप प्रधान और पानी समिति सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए, स्टोक के ग्रामीणों ने सर्दियों में तीन महीने तक सतही जल की अनुपलब्धता के प्रति अपनी चिंता जताई और सिंधु नदी, जो सिर्फ 3 किमी दूर है से साल भर सुनिश्चित पानी प्राप्त करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप की मांग की। स्टोक गांव में बसावट बिखरी हुई है, जिससे केंद्रीयकृत जल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करना मुश्किल हो गया। अधिक ऊंचाई के कारण बुनियादी ढाँचा बिछाने की लागत बहुत अधिक है।

राष्ट्रीय टीम की बुद्धिशीलता और विस्तृत विचार-विमर्श के कारण विभिन्न ग्राम पंचायत सदस्यों के विभिन्न विकल्पों की खोज की गई। अंत में, ऐसी लागत प्रभावी विकेन्द्रीकृत जल आपूर्ति योजना जो सतही स्रोत पर निर्भरता कम करती है, को मूर्त रूप दिया गया क्योंकि जमी हुई सतह के नीचे से जल ऊपर ले जाया जा सकता है।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने तीन विकल्पों पर चर्चा की और गांव वालों के पराशर्म से एक ऐसी इंफिल्ट्रेशन गैलरी संरचना विकसित करने का प्रास्तव किया जो उप-सतही जल को संचय करने में सहायक हो। गाँव में 28 हैंड पंप, और 11 सबमर्सिबल पंप हैं जो 33 सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट के करीब अवस्थित हैं। जमी हुई सतह से 1.5 मीटर नीचे का जल और भूजल सर्दियों में जमता नहीं था; इसलिए 17 हैंडपंप को सबमर्सिबल पंप में बदला जा सकता था। मौजूदा 10 सबमर्सिबल पंपों के उन्नयन की आवश्यकता है, और गाँव के सभी 410 घरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10 नए बोरवेल की आवश्यकता है।

सभी हैंडपंप और सबमर्सिबल पंप सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट (पीएसपी) के करीब अवस्थित थे। उन्हें पीएसपी से जोड़ा जाएगा जो बदले में गर्मियों के दौरान पानी उपलब्ध कराएंगे, और सर्दियों में भूमिगत जल समुदाय की जरूरतों को पूरा करेगा। इंफिल्ट्रेशन गैलरी के माध्यम से स्रोत वृद्धि से जमी हुई सतह के नीचे उप-सतही पानी को टैप करने में मदद मिलेगी और यह पूरे वर्षभर जल का स्रोत बना रहेगा।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली 31 स्थानीयकृत नेटवर्क क्षेत्र बनाएगी जिसमें व्यक्तिगत स्रोत (बोरवेल) है जो घरों के एक समूह के लिए जरूरत को पूरा करेगा। व्यक्तिगत समूहों के घरेलू मालिक अपने नेटवर्क का संचालन और रखरखाव करेंगे। इससे ग्रामीणों में विकसित बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारी और सह-स्वामित्व की भावना विकसित होगी।

ग्रामीण जलापूर्ति के लिए समर्पित हेल्पलाइन

पद्मिनी सुआर के लिए, यह आश्चर्य की बात थी कि एक साधारण फोन कॉल उसके नल से पानी के मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता था, जो इतने लंबे समय से सुस्त था। यह उससे कहीं अधिक था जो उसने माँगा था। ओडिशा के अनधिक विकसित खनन जिले क्योंझर से होने के कारण, उसने अब तक में इस तरह की सक्रिय और त्वरित कार्रवाई नहीं देखी है।

वह 18 लाख की आबादी वाली बूंजगाड़ा ग्राम पंचायत, क्योंझर की निवासी है, जिसमें से 86% आबादी ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जहां खदानों का सबसे अधिक धनत्व है। राज्य में कुल खनन रोजगार का 31% क्योंझर में केंद्रित है।

पद्मिनी को पिछले 2-3 दिनों से रुक-रुक कर पानी की आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा था। महामारी के परिदृश्य के बीच बिना किसी भी समाधान के उसने दूसरी तरफ से बहुत मदद की उम्मीद किए बिना जल हेल्पलाइन टोल-फ्री पर संपर्क किया। हालांकि, उसके आश्चर्य के लिए प्रतिक्रिया त्वरित थी। एक एसएमएस अलर्ट के माध्यम से, उसे एक शिकायत टिकट मिला, और आनंदपुर ब्लॉक के पीएचईडी अधिकारी को मौके पर जाकर वाल्व को साफ करने में बस कुछ समय लगा, जो पानी के प्रवाह को रोक रहा था। इसके तुरंत बाद, पानी का प्रवाह फिर से शुरू हो गया, और इस प्रकार पद्मिनी का सरकारी तंत्र पर भरोसा फिर कायम हो गया था, वह भी बिना कोई पैसा दिए। ओडिशा सरकार जल गुणवत्ता और सेवा देने के मानकों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से उनका प्रयास तेज हो गया है। एफएचटीसी के सार्वभौमिक कवरेज की दिशा में प्रयास करते हुए मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता का समाधान करना महत्वपूर्ण है। देश में अपनी तरह की प्रथम पहल में, समयबद्ध तरीके से नागरिकों की शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें दूर करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति के लिए एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1916 स्थापित किया गया है।

ओडिशा सरकार के 5टी (पारदर्शिता, टीमवर्क, प्रौद्योगिकी और समय के साथ परिवर्तन) मंत्र का उपयोग क्षेत्रीय परिवर्तन के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में किया जाता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल संरचना को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में बदलना है। ओडिशा द्वारा दिखाया गया रास्ता अन्य राज्यों द्वारा दोहराने के लायक है ताकि जनता का विश्वास पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध प्रतिक्रिया की सरकारी प्रणाली में और गहरा हो।

समुदाय प्रबंधित पेयजल कार्यक्रम: एकेआरएसपी का अनुभव

- श्री अपूर्व ओझा
(मुख्य कार्यकारी, एकेआरएसपी)

गुजरात में 1985 से और अपने अभियान की शुरुवात से, आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (भारत) अब 24 जिलों और 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में सक्रिय है। एकेआरएसपीआई का प्रारंभिक ध्यान विभिन्न संदर्भों, अर्थात् तटीय जूनागढ़, सूखा-ग्रस्त सुरेंद्रनगर, और आदिवासी भरूच/नर्मदा में प्राकृतिक संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन पर था। वाटरशेड और सिंचाई, सतही और भूजल पुनर्भरण पर बहुत काम किया गया। जैसे-जैसे ग्रामीण महिलाओं के साथ इसका काम बढ़ा, पेयजल एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में उभरा।

गुजरात

तटीय गुजरात और सूखाग्रस्त सुरेंद्रनगर की महिलाएं पानी लाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करती होंगी। माताओं के अस्वस्थ होने या छोटी बहनों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होने पर, युवा बेटियाँ अक्सर स्कूल जाने से चूक जाती होंगी। एक शिशु की हृदय विदारक कहानी थी, जब उसकी माँ पानी लाने के लिए कुण्ड पर गई थी तब वह एक सूखे

---

1 - रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वह तकनीक है जिसके माध्यम से छत के कैचमेंट से वर्षा जल को कैप्चर किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। टैंक का आकार आमतौर पर छत क्षेत्र, वर्षा की मात्रा और परिवार के आकार के आधार पर तय किया जाता है; हालांकि, 7,000 लीटर से 10,000-लीटर क्षमता भंडारण टैंक का सुझाव दिया गया है। भूमिगत टैंक आम तौर पर आरसीसी स्लैब के साथ कवर आकार में गोल होता है और टैंक से पानी खींचने के लिए एक पोटेबल हैंड पंप स्थापित किया जाता है। 2 फीट X 2 फीट का मैनहोल कवर स्लैब को कवर करने के लिए ऊपर लगाया जाता है ताकि इसके सफाई कार्यों के लिए जगह दी जा सके। यह संरचना गर्मी के मौसम में लाभार्थी परिवार की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।

कुएं में गिरकर मर गया था। एकेआरएसपीआई ने अपनी दान निधि से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स (आरआरडब्ल्यूएचएस)[1] की शुरुआत की थी, जिसमें एक अलग भागीदारी की आवश्यकता थी।

जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन (डब्ल्यूएएसएमओ) ने 2002 में संचालन शुरू किया और एकेआरएसपीआई ने 15 गांवों से 100 गांवों तक विस्तार में सहयोग किया।

एकेआरएसपीआई द्वारा संवर्धित महिला समूहों ने उत्साह के साथ नए हस्तक्षेप को अपनाया और सामुदायिक योगदान, ग्राम कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वयन के बाद रखरखाव में पंचायतों की मदद की। इस वजह से, उनकी आवाज़ पारंपरिक पुरुष-प्रधान पंचायतों में मजबूत हो जाती है, और कई पंचायत नेता भी बन गई हैं। सरकार के सहयोग से, एक 1,000 गांव कार्यक्रम खारे तटीय गांवों की अनूठी समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया था, कई अन्य लोग इस तटीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी) में शामिल हुए, जिससे टाटा ट्रस्ट्स, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और डब्ल्यूएएसएमओ को सफलतापूर्वक एक साथ लाया जा रहा है। एकेआरएसपीआई ने आरआरडब्ल्यूएचएस को वित्तीय सहायता के लिए सरकार को राजी करने के लिए 'प्रवाह' नामक एक अन्य एनजीओ नेटवर्क के साथ भी सहयोग किया, क्योंकि यह दूरदराज के घरों और खारे भूजल क्षेत्रों के लिए एकमात्र उपयुक्त तकनीक है। फिर से, डब्ल्यूएएसएमओ ने मदद की और हजारों ऐसे आरआरडब्ल्यूएचएस स्थापित किए गए। गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो ग्रामीणों को अपने स्वयं के आरआरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देता है।

बिहार

बिहार के कई हिस्सों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एक बड़ी समस्या रही है। ग्रामीण उत्तरी बिहार में, सतही हैंड पंप पीने के पानी का प्रमुख स्रोत (कुल स्टॉक का लगभग 87%) हैं। मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता कम होने के कारण, हैंडपंप का अपशिष्ट जल स्रोत के पास ही जमा हो जाता है,

जिससे यह अत्यधिक दूषित हो जाता है। स्थिर सतह का पानी, खराब स्वच्छता की स्थिति और जल स्रोतों के आसपास जल निकासी की अनुपस्थिति से स्थायी भूजल गंदा होता है।

इस पृष्ठभूमि में, एकेआरएसपी (भारत) ने 2009-10 में, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर दोनों जिलों में अपने नयी कार्य प्रणाली क्षेत्रों में जल स्रोतों की जांच की। परिणामों में लगभग 85 प्रतिशत स्रोतों में बैक्टीरिया के संदूषण का पता चला। इन परिणामों के आधार पर, उपचारात्मक और निवारक दोनों हस्तक्षेप किए गए थे जैसे कि जागरूकता सृजन और समुदायों में संवेदीकरण, हैंड पंपों के पास कंक्रीट प्लेटफार्मों का निर्माण और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए लघु जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।

इसके बाद, समुदाय के साथ काम करते हुए, एकेआरएसपीआई ने एक वैकल्पिक मॉडल विकसित करने की जरूरत महसूस की जो अत्यधिक-गरीबों को उनके स्वास्थ्य खर्चों में कमी लाने के उद्देश्य से सुरक्षित और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराएगा। इस संदर्भ में, एकेआरएसपी (भारत) ने समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों की दो अलग-अलग ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वामित्व वाली लघु पेयजल आपूर्ति प्रणाली (सीओएमडीडब्ल्यूएसएस) के दो अलग-अलग मॉडल का संचालन किया। यह नयी कार्य प्रणाली कम से कम अपव्यय के साथ पीने योग्य पानी 24x7 प्रदान करने के उद्देश्य से है। इसलिए, एक मॉडल उच्च घनत्व वाली आबादी वाली बसावटों के लिए डिज़ाइन किया गया था जिसमें बिखरी हुई बस्तियां थीं। इसमें, विभिन्न पोस्टों को विभिन्न बसावटों में लगाया गया और पीवीसी पाइपलाइनों के माध्यम से जोड़ा गया। प्रत्येक स्टैंड पोस्ट, दो ऑटो-लॉक नल और पानी को इकट्ठा करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्लेटफॉर्म से सुसज्जित था। स्टैंड पोस्ट स्थापित करने के इस मॉडल को बढ़ावा दिया गया और इसे स्वीकार किया गया।

समुदाय ने कुल अनुमानित लागत के 10% का नकद और श्रमिकों के योगदान के रूप में भुगतान किया और 100 रु. प्रति घर/माह का भुगतान करने पर सहमति जताई। इसमें जल संचालक की लागत, नलों के प्रतिस्थापन आदि और बिजली बिल शामिल थे। एक छोटी जल समिति, जिसमें स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि

के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ ने पूरी योजना का प्रबंधन किया। पहली सामुदायिक स्वामित्व वाली लघु पेयजल आपूर्ति योजना मई 2013 में पूसा ब्लॉक की कोरी पंचायत के मोहम्मदपुर में धोबी टोला में शुरू की गई थी। मॉडल के सफल प्रदर्शन के बाद, एकेआरएसपीआई ने सामुदायिक मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न बस्तियों में कई ऐसी योजनाओं की स्थापना की और पानी की गुणवत्ता पर भी जोर दिया।

RRWHS at Kamlapur village, Surendranagar

यह मॉडल बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के साथ साझा किया गया था और इनके कारकों को राज्य सरकार के सार्वभौमिक कवरेज कार्यक्रम के लिए अपनाया गया था। इसके बाद, इस मॉडल पर विभिन्न पंचायतों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एकेआरएसपीआई को एक संसाधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

जल गुणवत्ता परीक्षण: चूंकि पानी की गुणवत्ता हैंड पंप की अप्रभाविता का मुख्य कारण, अत: नियमित रूप से और निरंतर नए जल स्रोत का परीक्षण करना महत्वपूर्ण हो गया था। गाँव के नमूने भेजने के लिए जिला प्रयोगशाला बहुत दूर था और परिणाम जल्दी नहीं आते थे। इसलिए, एकेआरएसपीआई ने अपने कार्यालय एक छोटे से कमरे में एक लघु जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू करने का फैसला किया। 13 मापदंडों के लिए मानक उपकरण खरीदे गए, और योग्य स्थानीय युवा को नियुक्त किया गया। ग्रामीण स्तर पर खराब पानी की गुणवत्ता के स्वास्थ्य प्रभावों पर एक विशाल जागरूकता अभियान और जल समिति के नेतृत्व में प्रमुख लोगों के चलते, परीक्षण की मांग पैदा हुई और ग्रामीण 35 रुपये/ परीक्षण देने के लिए सहमत हुए। महिलाओं को जैविक परीक्षण के लिए H2S शीशियां बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया।

जेजेएम कोविड योद्धाओं ने लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध कराया साफ पानी

भारत कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है, इसलिए सरकार घरों में नल कनेक्शन प्रदान करके 'ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पेयजल की व्यवस्था' करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि लोगों को अपने घरों में पानी मिल सके। इसे पीने और अपनी दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी लाने हेतु सार्वजनिक स्टैंड-पोस्ट पर सार्वजनिक भीड़ से बचने के उपाय के रूप में लिया गया है।

जल योद्धा हाथ धोने के लिए घर पर पीने योग्य पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस से लड़ने और सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र समाधान के रूप में प्रचारित कर रहे थे, क्योंकि इससे कम लोग सार्वजनिक जल स्रोतों पर इकट्ठा होंगे।

लॉकडाउन के दौरान कोथल गांव में जल संरक्षण का काम

गरीब कल्याण रोजगार योजना, जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति से संबंधित कार्यों में स्थानीय लोगों और प्रवासियों को रोजगार देने को बढ़ावा दिया गया है। हजारों ऐसे लोग हैं, जो लॉकडाउन के दौरान शहरों से अपने गांवों/बसावटों में लौट आए हैं। जेजेएम ने उन प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, जो गांवों में वापस आ गए थे और काम की तलाश में थे। यह जल जीवन मिशन के अधिकारियों के लिए एक जीत की स्थिति थी, जिन्हें निर्माण, रेट्रो-फिटिंग और मरम्मत करने के लिए कुशल श्रम मिला, जबकि प्रवासियों को जल संबंधी निर्माण कार्यों के लिए पैसा मिला। यह कार्यक्रम इस संकट को कार्यक्रम और श्रम बल दोनों के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद अवसर में बदल रहा है। राज्यों ने जेजेएम के तहत लोगों को प्रासंगिक कार्यों के लिए चिनाई, प्लंबिंग और फिटिंग के प्रशिक्षण के लिए कौशल संवर्धन का कार्यक्रम शुरू किया है।

अरुणाचल प्रदेश के सुदूर गाँवों में जलापूर्ति योजनाओं की शुरूआत

भारत की पहली सौर-आधारित एकीकृत बहु-गाँव जलापूर्ति परियोजना (आईएमवीडब्ल्यूएसपी) अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई। दिबांग घाटी के निचली 39 गांवों को लाभान्वित करने वाली परियोजना पर 28.50 करोड़ रुपये का उपयोग हुआ। यह पूरे देश में 'अपनी तरह की पहली' परियोजना है। यह परियोजना 17,480 आबादी को पेयजल प्रदान करेगी। इसे पेयजल, हरित ऊर्जा और पर्यटन के कारकों के साथ एक एकीकृत परियोजना के रूप में तैयार किया गया है।

इस परियोजना में ग्रीन सोलर ग्रिड, स्काडा ऑटोमेशन प्रणाली, प्री-फैब्रिकेटेड जिंक फिटकिरी भंडारण टैंक और मेन, सब-मेन के लिए एचडीपीई कंडक्ट और संवितरण नेटवर्किंग प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस परियोजना में स्विमिंग पूल, एम्फी-थिएटर, फव्वारे और बैठने के लिए मनोरंजन पार्क शामिल हैं। यह परियोजना ऐसे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की परिकल्पना करती है जो लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाए और इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करे।

"जल परियोजना पार्क की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय ग्रामीणों ने पार्क में संपत्ति के प्रबंधन में जिम्मेदारी साझा करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

केंद्रीय मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पथरगांव, कैसू, एन्टेन और एन्टहेम गाँव को पेयजल योजना भी समर्पित की। जल जीवन मिशन के तहत 167 परिवारों को लाभान्वित करने वाली 0.17 एमएलडी पेयजल परियोजना का निर्माण किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "नामसाई अरुणाचल का अकेला प्रेरणात्मक जिला है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में पिछड़े आकांक्षी जिले उनके दिल के करीब हैं, इसलिए ऐसे जिलों में सभी प्रमुख कार्यक्रमों का विशेष रूप से कार्यान्वयन किया जाता है। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इनकी सीधे निगरानी की जाती है।"

श्री सिंह ने आशा व्यक्त की कि अगले नौ महीनों में, नामसाई जिले में सभी घरों के लिए पेयजल सुविधाओं का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नामसाई जैसे जिलों की मदद करने का अनुरोध किया, जो मॉनसून के दौरान बाढ़ का सामना करते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने नामसाई जिले में चोंगखाम में मरुआ पुल के पास, तेनग नदी के तट पर निर्माणाधीन लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना का भी दौरा किया। 1.7 एमएलडी क्षमता वाले शोधन संयंत्र का लक्ष्य चोंगखाम में 10 बसावटों में 1,285 परिवारों को कवर करते हुए 22,695 लोगों को साफ पेयजल मुहैया कराना है।

समाचारो में मिशन

पानी से छूटी रिश्तों में मिठास

मीठा पानी पहुंचा तो बरसों बाद बेटियों ने जोड़ा पीहर से नाता

हरिभूमि

भोपाल - मुख्य संस्करण

6 Nov 2020

अरुणाचल के दूरदराज गांव तक पहुंचा जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन: इस साल 20.69 लाख घरों तक पहुंचेगा नल से जल

स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में देंगे नल से पानी

Government launches 100-day campaign under Jal Jeevan Mission to ensure potable water supply in schools

PTI | Oct 2, 2020, 15:54 IST

NEW DELHI: The ministry of jal shakti on Friday launched a 100-day campaign to ensure potable water supply in all schools and anganwadi centers across the country.

Union jal shakti minister Gajendra Singh Shekhawat requested the states and

जल, जीवन, मिशन व शुद्ध जल

पंजाब की महिला सरपंच ने सभी के लिए पानी आंदोलन का किया नेतृत्व

जल जीवन मिशन' की योद्धा ने बदल दिया गांव को

सोलर लाइट लगाने की बन रही है योजना

flower show today as part of #AarogyaVan near Statue of Unity, #Gujarat. PM @narendramodi inaugurated the flower show and dedicated it to the nation.

@souindia

Solar-based lift water supply system is designed to provide drinking water to 39 census villages.

@PMOIndia @ArunachalCMO @PemaKhanduBJP

#HarGharJal

Translate Tweet

'हर घर जल' प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा

Tweet your reply

पीने के पानी के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है।

इस कार्यक्रम में जुड़े हम सभी जानते हैं कि गुजरात में पानी की क्या स्थिति थी।

बीते दो दशकों के प्रयासों से आज गुजरात उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है, जहां कोई पहले सोच भी नहीं सकता था: PM

Translate Tweet

11:25 · 24 Oct 20 · Twitter Web App

is our duty for their proper growth and holistic development. Let's work together to improve the lives of children and our future.

Jal Jeevan Mission

Har Ghar Jal

100 Days Campaign

12:14 · 15 Oct 20 · Twitter Web App

5 Retweets 10 Likes

Mission is glad to be able to join hands with locals and put their indigenous knowledge, and experience to greater use.

#HarGharJal #JalJeevanMission

Translate Tweet

पीएम ने जल जीवन मिशन को सराहा

19:41 · 23 Oct 20 · Twitter Web App

Tweet your reply

Gajendra Singh Shekhawat

@gssjodhpur

Together we will be setting up a decentralised water supply system that will remain functional even during sub-zero temperature.

@jaljeevan_

The #ICTGrandChallenge2020 launched by @jaljeevan_ in partnership with @GoI_MeitY received impressive response. This opportunity will harness vibrant IoT eco-system of India to measure and monitor the service delivery of the water supply in rural areas.

pib.gov.in/Press

Adobe Spark

हर घर जल
जल जीवन मिशन

गणतंत्र दिवस परेड 2020 की उत्कृष्ट झांकी

जल जीवन मिशन
हर घर जल

हर घर जल
जल जीवन मिशन

हर घर जल संवाद

आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र देश के हर हिस्से, हर नागरिक के विश्वास का मंत्र बन चुका है। आज देश के हर जन, हर क्षेत्र को लग रहा है कि उस तक सरकार पहुंच रही है और वो भी देश के विकास में भागीदार है।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें

Jal Jeevan Mission, India
@jaljeevan_
Jal Jeevan Mission
@jaljeevanmission
jjm.gov.in

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल और स्वच्छता विभाग
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
नई दिल्ली - 110 003
ई-मेल: njjm-ddws@gov.in